



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1992 (भाद्रपद 21, 1914)

No. 37]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1992 (BHADRA 21, 1914)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संबंधित जनों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिस्से अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)
733	
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
967	
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
11	935
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खण्ड 2—वेस्टेड कार्यालय द्वारा जारी की गई वेस्टेडों और विज्ञापनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस
1673	1097
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, प्रख्यादेश और विनियम	भाग III—खण्ड 3—मुख्य व्यक्तियों के प्राधिकार के अधीन कथन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
*	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, प्रख्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
*	3237
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
*	145
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संबंधित जनों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	भाग V—प्रदेशी और हिन्दी दोनों में ज.स. और ज.स. के आदेशों तथा अनुपूरक
*	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संबंधित जनों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
*	

\*अंकित प्राप्त नहीं

## CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	733	PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	967	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	935
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1573	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1097
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3237
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	145
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## इलेक्ट्रानिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1992

## संकल्प

सं० 1(1)/91-हि० अ०—इलेक्ट्रानिकी विभाग के दिनांक 16 जुलाई 1985 के संकल्प सं० 1(1)/84-हि० अ० द्वारा गठित तथा दिनांक 16-1-1989 के संकल्प सं० 1(1)/87-हि० अ० के जरिए अंतिम बार पुनर्गठित इलेक्ट्रानिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, भारत सरकार ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध से इन विभागों को सलाह देने के उद्देश्य से उक्त समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। समिति का गठन, उसके कार्य, आवि नीचे दिए अनुसार होंगे :—

## 1. गठन

1. इलेक्ट्रानिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री

अध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

लोक सभा के सदस्य

2. श्री गोपी नाथ गजपति

सदस्य

3. प्रो० आर० आर० प्रामाणिक

सदस्य

राज्य सभा के सदस्य

4. श्री शमीम हाशमी

सदस्य

5. श्री सुनील बसुराय

सदस्य

संसदीय राज्यभाषा समिति के सदस्य

6. श्री राम विभास पासवान, संसद सदस्य (लोकसभा)

सदस्य

7. श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य (लोकसभा)

सदस्य

अन्य गैर सरकारी सदस्य

8. श्री बी० शोबन, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिवर्धन, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

सदस्य

9. श्री द्वारका दास जी बेव, प्रधान मंत्री राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

सदस्य

10. डा० रत्नाकर पांडेय, संयोजक, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी

सदस्य

11. प्रो० सी० एस० झा, कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

सदस्य

12. डा० नामवर सिंह, प्रख्यात समालोचक एवं साहित्यकार

सदस्य

13. डा० अजित राम वर्मा, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली

सदस्य

14. प्रो० हरि मोहन गुप्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य

15. डा० जगमल सिंह, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल

सदस्य

16. श्री टी० रामाकृष्ण मूर्ति, आन्ध्र प्रदेश हिन्दी अकादमी, हैदराबाद

सदस्य

17. श्री आर० डी० शर्मा, मुख्य संपादक 'कृषि', भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली

सदस्य

सरकारी सदस्य

18. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग

सदस्य

19. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग

सदस्य

20. सचिव, अंतरिक्ष विभाग

सदस्य

21. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

सदस्य

22. वैज्ञानिक सचिव, इसरो, बंगलूर

सदस्य

23. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग

सदस्य

24. अपर सचिव, अंतरिक्ष विभाग

सदस्य

25. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

सदस्य

26. संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग

सदस्य

27. संयुक्त सचिव, अन्तरिक्ष विभाग	सदस्य
28. संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	सदस्य
29. वरिष्ठ निदेशक (कम्प्यूटर विकास विभाग), इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	सदस्य
30. महानिदेशक, मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	सदस्य
31. निदेशक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम	सदस्य
32. निदेशक, इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलूर	सदस्य
33. निदेशक, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद	सदस्य
34. निदेशक, विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट (बैक) अहमदाबाद	सदस्य
35. निदेशक, भार केन्द्र, श्रीहरीकोटा	सदस्य
36. निदेशक, इसरो त्रुमिति अनुसर्जन केन्द्र तथा आवेश संचाराल (इस्टैक), बंगलूर	सदस्य
37. निदेशक, श्व मोदन प्रणाली केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम	सदस्य
38. मुख्य इंजीनियर, सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अन्तरिक्ष विभाग, बंगलूर	सदस्य
39. प्रबन्ध निदेशक, न्युक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	सदस्य
40. प्रबन्ध निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	सदस्य
41. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, युरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	सदस्य
42. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन रेयर अर्ब्स लि०	सदस्य
43. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, सीएमसी लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
44. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि०, मोहाली (पंजाब)	सदस्य
45. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली	सदस्य
46. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में हिन्दी के कार्य से संबंधित संयुक्त सचिव/निदेशक	सदस्य-सचिव

## 2. समिति के कार्य

यह समिति केन्द्रीय हिन्दी भाषा समिति और राजभा, विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों के अनुसार ऊर्जा विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग के कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करेगी और इस संबंध में आवश्यक सलाह देगी।

## 3. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन तीन वर्ष का होगा।

(क) जो संसद सदस्य इस संसद सभित के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेंगे।

## 4. सामान्य

(1) समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोगित सदस्यों के रूप में नामित कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है।

(2) समिति का मुख्यालय तब दिल्ली में होगा। किन्तु समिति अपनी बैठके आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

## 5. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और डैनिक भत्ते दिए जायेंगे।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों, सब राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के निदेशक तथा महासेवा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

एस० मुरली, संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 1992

## आदेश

विषय :—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कुष्णा-गोदावरी बेसिन ब्लॉक आई० एफ० (अपतदीय) क्षेत्र के 790 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ० 12012-39-91--ओ० एन० डी० ओ०-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 8 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, बेहुराबून को (जिसे इससे पश्चात् आयोग कहा गया है) कुष्णा-गोदावरी बेसिन ब्लॉक आई० एफ० अपतदीय क्षेत्र के 790 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 20 सितम्बर, 1991 (20-0-91) से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संघर्ष में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण स्वीरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व ब्लॉक (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :-

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैमिंग हैड कन्डिसेट पर 314 रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी ।

स्वत्व ब्लॉक (रायल्टी) की अवायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को ली जाएगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अन्वेषण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैमिंग हैड कन्डिसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ब" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/- रुपये की धनराशि प्रतिवृत्ति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक ब्लॉक का कृतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ष किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :-

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/- रुपये
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 400/- रुपये
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/- रुपये
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/- रुपये
5. लाइसेंस के मशीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600/- रुपये ।

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किए जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक रिपोर्ट गुप्त रूप से लेगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिणामों, अध्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की "तलछटी" और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी विचारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन

बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मआवजा देगा जितना आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) पर पेट्रोलियम गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के-बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो अपनटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग खार्च अन्वेषी आपरेशनों संबंधी संचालनों के दौरान एकत्र किए गए बायीमिट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रखा मन्त्रालय, नोसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ।

(ड) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाने होंगे ।

(ण) यदि विदेशी जलपोन को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में से जलपत्तों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो ।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र-विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयारी की गई सम्पूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

अनुसूची "क"

कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक आई—एक अर्पटीय क्षेत्र के लिए 790 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक निर्देशांक :

ज्वाइंट	अक्षांतर	देशांतर
के	16° 28' 57"	82° 06' 45"
एल	16° 10' 51"	81° 47' 48"
एम	16° 09' 39"	81° 47' 48"
एन	16° 14' 33"	82° 06' 45"

अनुसूची—“ख”

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मुख्य सहित भासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हेड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्वारा मैं ..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर—

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

एम० भाटिन  
ईस्क अधिकारी

विभाग 7 अगस्त 1992

विषय : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को बम्बई अपतटीय बी-180 संरचना क्षेत्र के 10 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

आवेश

सं० ओ० 12012/48/91-ओ० एम० जी० डी०-4-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) बम्बई अपतटीय बी-180 संरचना क्षेत्र के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम खनन की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 22 नवम्बर, 1991 (22-11-1991) से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

- (क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।
- (ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाए गये तो आयोग पूर्ण व्योम के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।
- (ग) स्वस्थ शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :—
  - (i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैब्र कन्डेन्सेट पर 314 रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर पर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
  - (ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।
 स्वस्थ शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संजालय नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी।
- (घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैब्र कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा।
- (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/- रुपये की धन-राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।
- (च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संयोजना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किमी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :—

- (1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/- रुपये
- (2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40/- रुपये
- (3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/- रुपये
- (4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/- रुपये
- (5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 800/- रुपये।

- (छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से लेगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की "तलछटी" और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर वस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग खर्चा/अन्वेषी आपरेषनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बायोमीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा संजालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं।

(ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाता चाहिए ताकि निरीक्षण बल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई सम्पूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रो-ग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश तथा उनके नाम पर।

एम० माटन  
हैक अधिकारी

अनुसूची "क"

बम्बई अपतटीय बी-180 संरचना क्षेत्र के लिए 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भौगोलिक निर्देशांक।

प्वाइंट	अक्षांतर	देशान्तर
ए	18° 56' 37"	72° 11' 08.0"
बी	18° 55' 43"	72° 12' 25.0"
सी	18° 54' 06"	72° 11' 07.0"
डी	18° 55' 00"	72° 10' 00.0"

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग कम्बेस्टर तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मुख्य महित मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लीटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोचित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को बढ़ाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हेड कम्बेस्टर

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लीटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोचित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को बढ़ाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लीटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोचित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को बढ़ाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्वारा मैं ..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस विवरण में की गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं कुछ अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर .....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

एक-माहिन  
का अधिकारी



सञ्चार सञ्चालक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जुन 1992

विषय :—राष्ट्रिय बीमा निधि नियमावली के नियम 2 में संशोधन, डाक और बीमा निधि योजनाओं के लिए अस्थाई कर्मचारियों की पात्रता।

सं० 26-57/88-एल आई०—डाक और बीमा निधि नियमावली के नियम 2 के निम्नलिखित मौजूबा उपनियमों को सरकार प्रकाश में निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाए :—

उपनियम (4) मूल नियम 9(14) में परिभाषित किए अनुसार "स्थानीय निधि" से भुगतान पाने वाले स्थाई और अस्थाई कर्मचारी।

उपनियम (8) सरकार द्वारा और सरकार की देखरेख में स्थापित भारतीय विपणनस्थलों के सभी स्थाई और अस्थाई कर्मचारी।

उपनियम (14) सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सभी स्थाई और अस्थाई कर्मचारी।

उपनियम (15) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सभी स्थाई और अस्थाई कर्मचारी।

उपनियम (16) भारतीय मानक संस्थाओं के सभी स्थाई और अस्थाई कर्मचारी।

उपनियम (17) व मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, व डेंटल काउंसिल आफ इंडिया, व नर्सिंग काउंसिल आफ इंडिया और व फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया के सभी स्थाई और अस्थाई कर्मचारी।

उपनियम (23) निम्नलिखित संस्थाओं के सभी स्थाई और अस्थाई कर्मचारी :—

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक निधि प्रायोग।

(घ) काफी योद्ध।

(ङ) रबर बोर्ड।

(च) खादी और ग्रामोद्योग आयोग।

(छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और इसके अधीनस्थ संगठन।

(ज) सार्वजनिक निधि संगठन।

(झ) महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम।

(ण) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

कृपया पत्र की पावनी भेजें।

एस० सी० शर्मा  
निदेशक (पी० एल० आई०)

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th August 1992

## CORRIGENDUM

No. 107-Pres/92.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 77-Pres/92, dated 26th May, 1992, published in Part-I Section-1 of the Gazette of India, dated 27th June 1992 relating to the award of President's Police Medal for gallantry to Shri Dalbir Singh, Inspector of Police :—

## AT PAGE 1

*For*—The President is pleased to award the *Police Medal for gallantry* to the undermentioned officer of Punjab Police.

*Read*—The President is pleased to award the *President's Police Medal for gallantry* to the undermentioned officer of Punjab Police.

## AT PAGE 2

*For*—This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of *Police Medal* and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th August, 1990.

*Read*—This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of *President's Police Medal* and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25th August, 1990.

A. K. UPADHYAY,  
Director

## DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi-110003, the 10th August 1992

## RESOLUTION

No. 1(1)/91-H.S.—On the expiry of the three-year term of the *Joint Hindi Advisory Committee* for the Department of Electronics, Atomic Energy and Space constituted vide this Department's Resolution No. 1(1)/84-H.S. dated 16-7-1985 and reconstituted last time vide Resolution No. 1-8)/87-H.S. dated 16-1-1989, the Govt. of India have decided to reconstitute the said Committee with a view to advising these Departments with regard to progressive use of Hindi. Composition of the Committee, its functions etc. would be as under :—

## 1. Composition

## Chairman

1. Minister in-charge for the Departments of Electronics, Atomic Energy and Space.

## Non-Official Members

## Members of Parliament from Rajya Sabha

2. Shri Gopinath Gajapati.
3. Prof. R.R. Pramanik.

## Members of Parliament from Rajya Sabha

4. Shri Shamim Hashmi.
5. Shri Sunil Basuroy.

## Members from Committee of Parliament on Official Language

6. Shri Ram Vilas Paswan,  
Member of Parliament (Lok Sabha)
7. Shri Uday Pratap Singh,  
Member of Parliament (Lok Sabha).

## Other Non-Official Members

8. Shri V. Seshan, Representative of  
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi.

9. Shri Dwarka Das G. Ved, Pradhan Mantri, Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Wardha.
10. Dr. Ratanakar Pandey, Convenor, Nagri Pracharini Sabha, Varanasi.
11. Prof. C. S. Jha, Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Varanasi-221 005.
12. Dr. Namvar Singh, Well-known Critic & Literateur.
13. Dr. Ajit Ram Verma, Ex-Director, National Physical Laboratory, New Delhi.
14. Prof. Harimohan Gupta, IIT, Delhi.
15. Dr. Jagnal Singh, Manipur University, Imphal.
16. Shri T. Radhakrishna Murthy, Andhra Pradesh Hindi Academy, Hyderabad.
17. Shri R. D. Sharma, Chief Editor, 'Krishi', IARI, Pusa, New Delhi.

*Official Members*

18. Secretary, Department of Atomic Energy.
19. Secretary, Department of Electronics.
20. Secretary, Department of Space.
21. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India.
22. Scientific Secretary, ISRO, Bangalore.
23. Additional Secretary, Deptt. of Atomic Energy.
24. Additional Secretary, Department of Space.
25. Joint Secretary, Deptt. of Official Language.
26. Joint Secretary, Deptt. of Atomic Energy.
27. Joint Secretary, Department of Space.
28. Joint Secretary (Pers), Department of Electronics.
29. Senior Director (Computer Development Division), Department of Electronics.
30. Director General, STQC, Deptt. of Electronics.
31. Director, VSSC, Trivandrum.
32. Director, ISRO, Satellite Centre, Bangalore.
33. Director, Space Application Centre, Ahmedabad.
34. Director, Development and Educational Communication Unit (DECU), Ahmedabad.
35. Director, SHAR Centre, Sriharikota.
36. Director, ISRO Telemetry Tracking and Command Network (ISTRN), Bangalore.
37. Director, Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), Trivandrum.
38. Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space, Bangalore.
39. Managing Director, Nuclear Power Corporation of India Ltd.
40. Chairman-cum-Managing Director, Electronics Corporation of India Ltd.

41. Chairman-cum-Managing Director, Uranium Corporation of India Ltd.
42. Chairman-cum-Managing Director, Indian Rare Earths Ltd.
43. Chairman-cum-Managing Director, CMC Ltd., New Delhi.
44. Chairman-cum-Managing Director, SCI Ltd., Mohali (Punjab).
45. Chairman-cum-Managing Director, ET&T Corpn. Ltd.

*Member-Secretary*

46. Joint Secretary/Director in-charge of Hindi work in Deptt. of Electronics.

*2. Functions of the Committee*

The Committee will review the progress made and advise the Departments of Atomic Energy, Electronics and Space on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes in accordance with the policies framed by Central Hindi Committee and Department of Official Language from time to time.

*3. Tenure*

The term of the Committee will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :

- (a) Members of Parliament who are members of the Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Parliament.
- (b) Ex-officio members of the Committee shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Committee.
- (c) If a vacancy arises on the Committee due to resignation or death of a member, the member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term.

*4. General*

- (i) The Committee may nominate additional members as co-opted members and invite experts to attend its meetings as may be considered necessary.
- (ii) The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi, but it may hold its meetings at any out station also.

*5. Travelling and other allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee at the rates prescribed by the Government of India from time to time.

**ORDER**

**ORDERED** that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Committee, all State Governments

and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. MURALI,  
Jt. Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 31st July 1992

### ORDER

SUBJECT :—*Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Krishna Godavari Basin Block I F (Offshore) area measuring 790 sq. kms.*

No. O-12012/39/91-ONG D IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Rules 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (hereinafter referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 20th September, 1991 (20-9-1991) for Krishna Godavari Basin Block I F Offshore area measuring 790 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

- (a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.
- (b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.
- (c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :
  - (i) Rs. 314/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time, on all crude oil and casing-head condensate.
  - (ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time. The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.
- (d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.
- (e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.
- (f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—
  - (i) Rs. 8/- for the first year of the licence;
  - (ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;
  - (iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
  - (iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
  - (v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal.
- (g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.
- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.
- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.
- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.
- (l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.
- (m) The Commission should ensure security of oceanographic data.
- (n) The entire data is processed in India.
- (o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.
- (p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this areas is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

### SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of Krishna Godavari Basin Block I—F—Offshore area measuring 790 Sq. kms.

Point	Latitude	Longitude
L	16° 28' 57"	82° 06' 45"
L	16° 20' 51"	81° 47' 48"
M	16° 09' 39"	81° 47' 48"
N	16° 14' 33"	82° 06' 45"

## SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas  
Produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

## A.—Crude Oil

Total No. of Metric tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Govern- ment	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

## B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or return- ed to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

## C—Natural Gas

Total Number of cubic Metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum explo- ration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri—do hereby solemnly and sincerely declare, and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

(Signature)

M. MARTIN, Desk Officer

The 7th August 1992

## ORDER

**SUBJECT :—***Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Bombay Offshore B-180 structure area measuring 10 sq. kms.*

No. O-12012/48, 91-ONG D 4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 22nd Nov. 1991 (22-11-1991) for Bombay Offshore B-180 structure area measuring 10 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

- (a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.
- (b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.
- (c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :
  - (i) Rs. 314/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.
  - (ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.
- (d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.
- (e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.
- (f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

- (i) Rs. 8/- for the first year of the licence;
- (ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;
- (iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
- (iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
- (v) Rs. 600/- for the first and second years of renewal.

- (g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.
- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all time and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.
- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.
- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.
- (l) The Commission should render Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations, survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.
- (m) The Commission should ensure security of oceanographic data.
- (n) The entire data is processed in India
- (o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.
- (p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

Geographical coordinates of Bombay Offshore B-180 structure area measuring 10 Sq. kms.

Point	Latitude	Longitude
A	18° 56' 37"	72° 11' 08.0"
B	18° 55' 43"	72° 12' 25.0"
C	18° 54' 06"	72° 11' 07.0"
D	18° 55' 00"	72° 10' 00.0"

## SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas

Produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

## A—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

## B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

## C—Natural Gas

Total Number of cubic Metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri—do hereby solemnly and sincerely declare, and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India

(Signature)

M. MARTIN, Desk Officer

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPTT. OF POSTS)

New Delhi-110001, the 17th June 1992

**SUB :—Amendment to Rule 2 of POIF Rules—Eligibility of Temporary Employees for Post Office Insurance Fund Schemes.**

No. 26-57/88-LI.—The following existing sub Rules of Rule 2 of POIF Rules may be amended/substituted as under with immediate effect.

*Sub rule (4)*—Permanent and temporary servants paid from "local funds" as defined in fundamental Rules 9(14)

*Sub rule (8)*—All permanent and temporary servants of Universities in India established by Government and under Government supervision.

*Sub rule (14)*—All permanent and temporary servants of Government aided educational institutions.

*Sub rule (15)*—All permanent and temporary servants of the Council of Scientific and Industrial Research.

*Sub rule (16)*—All permanent and temporary servants of the Indian Standards Institutions.

*Sub rule (17)*—All permanent and temporary servants of—The Medical Council of India, the Dental Council of India, the Nursing Council of India and the Pharmacy Council of India.

*Sub rule (23)*—All permanent and temporary employees of—

- (a) Employees State Insurance Corporation.
- (b) Employees State Insurance.
- (c) Central P. F. Commission.
- (d) Coffee Board.
- (e) Rubber Board.
- (f) Khadi and Village Industries Commission.
- (g) ICAR and its subordinate Organisations.
- (h) Provident Fund Organisation.
- (i) Maharashtra State Roadways Transport Corporation.
- (j) UP State Roadways Transport Corporation.

S. C. SARMA,  
Director (PLI)

